छिंदवाड़ा -बैतूल हाईवे पर भीषण हादसा : ट्रक ने मजदूरों से भरी पिकअप को मारी टक्कर, 5 की मौत

छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा-बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच मजदूरों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 अन्य मजदूर घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब मजदूरों से भरी एक पिकअप वाहन को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मजदूरों से भरी पिकअप छिंदवाड़ा से बैतूल की ओर जा रही थी। वाहन में बड़ी संख्या में मजदूर सवार थे, जो रोजगार के सिलसिले में यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान हाईवे पर तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने पिकअप को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार मजदूर सड़क पर जा गिरे।

हादसे में पांच मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग 20 लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं। स्थानीय लोगों ने भी राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग किया और घायलों को वाहन से बाहर निकालने में मदद की।

सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। गंभीर रूप से घायल कुछ मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। चिकित्सकों की टीम लगातार घायलों की निगरानी कर रही है।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की रफ्तार काफी अधिक थी और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। हालांकि पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ट्रक चालक की तलाश की जा रही है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है।

घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। कई परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि मृतकों में अधिकांश मजदूर अपने परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य थे। अस्पताल में परिजनों और रिश्तेदारों की भीड़ जुटी रही।

प्रशासनिक अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और उपचार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों को हरसंभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है।

यह हादसा एक बार फिर मजदूरों के असुरक्षित परिवहन और हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों के खतरे को उजागर करता है। आए दिन होने वाली ऐसी दुर्घटनाएं सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से हाईवे पर यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने और मजदूरों के सुरक्षित परिवहन के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया जारी है। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है।

उरधन खुली खदान ने रचा नया कीर्तिमान, बिना कोयला स्टॉक में आग लगे हुआ शत-प्रतिशत उत्पादन एवं डिस्पैच

छिंदवाड़ा। उरधन खुली खदान (**OCM**) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए शत-प्रतिशत कोयला उत्पादन एवं डिस्पैच का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा किया। विशेष बात यह रही कि पूरे वर्ष के दौरान कोयला स्टॉक में आग लगने की कोई घटना नहीं हुई और सुरक्षित रूप से कोयले का डिस्पैच किया गया।

इस सफलता के पीछे उरधन खदान के माइन मैनेजर **Sandeep Washington** एवं उनकी पूरी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गत वर्ष स्थानांतरित होकर आए श्री वाशिंगटन ने अपने अनुभव, कुशल प्रबंधन एवं प्रभावी निगरानी के माध्यम से कोयला स्टॉक में आग लगने जैसी गंभीर समस्या पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया।

गौरतलब है कि उरधन क्षेत्र में पूर्व वर्षों में कोयला स्टॉक में आग लगने की घटनाएं होती रही हैं, जिससे कंपनी को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। कोयला खदानों एवं स्टॉकों में आग लगना उद्योग के लिए एक गंभीर चुनौती माना जाता है और इससे उत्पादन व संसाधनों को नुकसान पहुंच सकता है। इस उपलब्धि में क्षेत्र के महाप्रबंधक (जीएम) का मार्गदर्शन एवं सहयोग भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उनके नेतृत्व में खदान प्रबंधन ने सुरक्षा, उत्पादन एवं डिस्पैच व्यवस्था को बेहतर बनाते हुए उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए।

उरधन क्षेत्र की जनता, श्रमिकों एवं विभिन्न श्रमिक संगठनों ने इस सराहनीय कार्य के लिए माइन मैनेजर श्री संदीप वाशिंगटन, उनकी टीम तथा क्षेत्रीय प्रबंधन को बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापित किया है। सभी ने आशा व्यक्त की है कि भविष्य में भी इसी प्रकार सुरक्षित एवं उत्कृष्ट कार्य संस्कृति के माध्यम से खदान नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी।

राजस्व स्टांप के नाम पर खुली लूट! छिंदवाड़ा में 100 का स्टांप 150 तक बिकने के आरोप, जनता पूछ रही—कब रुकेगा यह खेल?

छिंदवाड़ा। जिले में राजस्व स्टांप की बिक्री को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आम नागरिकों, किसानों, मजदूरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से लगातार ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं कि निर्धारित मूल्य ₹100 वाले राजस्व स्टांप के लिए उनसे ₹130 से ₹150 तक वसूले जा रहे हैं। आरोप है कि स्टांप विक्रेताओं द्वारा कृत्रिम कमी का माहौल बनाकर मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं, जबकि प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है।

जिले के कई तहसील मुख्यालयों, उप पंजीयक कार्यालयों और स्टांप विक्रय केंद्रों पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग शपथ पत्र, अनुबंध, बैंकिंग कार्य, भूमि संबंधी दस्तावेज और अन्य सरकारी औपचारिकताओं के लिए राजस्व स्टांप खरीदने पहुंचते हैं। लेकिन जरूरतमंद नागरिकों का आरोप है कि निर्धारित मूल्य पर स्टांप उपलब्ध नहीं कराए जा रहे और अतिरिक्त राशि देने पर ही स्टांप मिल पाते हैं।

कृत्रिम कमी बनाकर वसूली का आरोप

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई स्थानों पर स्टांप उपलब्ध होने के बावजूद कमी का हवाला दिया जाता है। इसके बाद जरूरतमंद लोगों को अधिक कीमत पर स्टांप बेच दिए जाते हैं। खास बात यह है कि अधिकांश लोग अपने जरूरी कामों के कारण मजबूरी में अधिक भुगतान कर देते हैं, क्योंकि उन्हें उसी दिन दस्तावेजी कार्य पूरा करना होता है।

ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले किसानों और मजदूरों का कहना है कि उन्हें पहले से ही यात्रा, टाइपिंग, नोटरी और अन्य खर्चों का बोझ उठाना पड़ता है। ऐसे में यदि ₹100 के स्टांप के लिए ₹150 तक चुकाने पड़ें तो उनकी जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है।

सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब और ग्रामीण वर्ग

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कथित अनियमितता का सबसे ज्यादा असर गरीब, किसान, मजदूर और ग्रामीण नागरिकों पर पड़ता है। शहर के जागरूक लोग तो शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन गांवों से आने वाले अधिकांश लोग व्यवस्था के सामने खुद को असहाय महसूस करते हैं।

कई लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, जिसके कारण ऐसे तत्वों के हौसले बुलंद बने रहते हैं। यही वजह है कि वर्षों से यह समस्या समय-समय पर सामने आती रही है।

प्रशासनिक निगरानी पर उठ रहे सवाल

यदि वास्तव में निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूली जा रही है तो यह सवाल भी उठना स्वाभाविक है कि संबंधित विभाग और प्रशासनिक अधिकारी इसकी निगरानी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। राजस्व स्टांप की बिक्री एक नियंत्रित व्यवस्था के तहत होती है, ऐसे में खुलेआम अधिक मूल्य वसूले जाने के आरोप गंभीर जांच का विषय हैं।

जनता पूछ रही है कि—क्या स्टांप की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है? यदि स्टांप उपलब्ध हैं तो अधिक कीमत क्यों ली जा रही है? शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?क्या जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जा रहा है?

क्या दोषी पाए जाने वालों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे?

करोड़ों के कारोबार पर निगाह जरूरी

जानकारों का कहना है कि राजस्व स्टांप और दस्तावेजी कार्यों का कारोबार करोड़ों रुपये का है। यदि छोटे-छोटे स्तर पर भी निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूली जा रही है, तो लंबे समय में यह रकम काफी बड़ी हो सकती है। इसलिए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है ताकि वास्तविक स्थिति जनता के सामने आ सके।

जनता की मांग—हो निष्पक्ष जांच

छिंदवाड़ा जिले के नागरिकों ने मांग की है कि जिला प्रशासन, कलेक्टर और संबंधित राजस्व विभाग इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएं। स्टांप विक्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जाए, निर्धारित मूल्य सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कराई जाए और यदि कहीं अधिक राशि वसूली जा रही हो तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

बड़ा सवाल

आज छिंदवाड़ा की जनता जानना चाहती है कि क्या ₹100 का राजस्व स्टांप वास्तव में ₹100 में उपलब्ध होगा या फिर आम नागरिकों को इसी तरह अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ेगी? क्या प्रशासन इस कथित लूट पर लगाम लगाएगा? क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी?

फिलहाल यह मुद्दा आमजन की जेब से जुड़ा हुआ है और लोग प्रशासन से केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं। छिंदवाड़ा पूछ रहा है—राजस्व स्टांप के नाम पर हो रही इस कथित लूट पर आखिर कब लगेगी रोक?

रेत माफियाओं के आगे बेबस प्रशासन! दिन-दहाड़े हो रहा अवैध उत्खनन, जिम्मेदारों की चुप्पी पर उठे सवाल

छिंदवाड़ा। जिले में अवैध रेत उत्खनन का कारोबार एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। नदियों और घाटों से दिन-दहाड़े भारी मशीनों और वाहनों के माध्यम से रेत निकाली जा रही है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि अवैध उत्खनन का यह खेल लंबे समय से चल रहा है और शिकायतों के बावजूद कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रह जाती है। अवैध खनन के कारण नदियों का स्वरूप बदल रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और शासन को करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है।

जानकारों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में खनन की अनुमति नहीं है, वहां भी खुलेआम रेत निकाली जा रही है। कई स्थानों पर रात के बजाय अब दिन में भी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और डंपर बेखौफ दौड़ते देखे जा सकते हैं। इससे यह सवाल उठ रहा है कि आखिर रेत माफियाओं को किसका संरक्षण प्राप्त है कि वे प्रशासनिक कार्रवाई के भय के बिना काम कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नदी तटों पर लगातार हो रहे उत्खनन से जलस्तर प्रभावित हो रहा है। बरसात के मौसम में कटाव बढ़ने की आशंका है और कई स्थानों पर खेतों तथा ग्रामीण मार्गों को भी नुकसान पहुंच रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञ भी लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि अनियंत्रित रेत खनन से नदियों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, जिससे भविष्य में जल संकट और गंभीर हो सकता है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रशासन के पास राजस्व, खनिज, पुलिस और स्थानीय निकायों का पूरा अमला मौजूद है, तब भी अवैध उत्खनन पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति हुई। कुछ वाहनों की जब्ती और मामूली जुर्माने के बाद पूरा कारोबार फिर पहले की तरह शुरू हो जाता है। इससे माफियाओं के हौसले और बुलंद हो रहे हैं।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में समय-समय पर अवैध रेत खनन को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। कई मामलों में प्रशासन को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करनी पड़ी है, जबकि कहीं-कहीं अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमले तक हुए हैं। यह दर्शाता है कि अवैध खनन केवल राजस्व हानि का मामला नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और पर्यावरण सुरक्षा से भी जुड़ा गंभीर विषय है।

छिंदवाड़ा जिले में भी पहले अवैध रेत भंडारण और उत्खनन को लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा विरोध दर्ज कराया जा चुका है। आरोप लगाए गए थे कि रेत का अवैध भंडारण सार्वजनिक स्थलों तक में किया जा रहा है और संबंधित विभाग मूकदर्शक बना हुआ है। ऐसे मामलों के बाद भी यदि स्थिति में सुधार नहीं आता, तो यह प्रशासनिक इच्छाशक्ति पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन चाहे तो अवैध उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। जिले की सीमाओं पर चेकपोस्ट, नियमित निरीक्षण, ड्रोन निगरानी और संयुक्त कार्रवाई के माध्यम से इस अवैध कारोबार को काफी हद तक रोका जा सकता है। प्रदेश के अन्य जिलों में बड़े स्तर पर छापेमारी कर दर्जनों वाहन जब्त किए जाने के उदाहरण भी सामने आ चुके हैं।

अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेंगे या फिर रेत माफियाओं का यह खेल यूं ही चलता रहेगा? आखिर कब तक नदियों की छाती छलनी होती रहेगी और शासन को राजस्व का नुकसान होता रहेगा? जनता जवाब चाहती है कि दिन-दहाड़े हो रहे इस अवैध उत्खनन के पीछे कौन लोग हैं और उन पर कार्रवाई कब होगी?

रेत माफियाओं के बढ़ते हौसलों और प्रशासनिक निष्क्रियता के बीच आम लोगों की निगाहें अब जिला प्रशासन और खनिज विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले दिनों में यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है।

खबर संक्षेप

राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पहुंची मंडला ली बैठक, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

मण्डला। वनवासी विकास परिषद की एक दिवसीय बैठक में डॉ. रेखा नागर राष्ट्रीय कार्यकारिणी टोली सदस्य एवं श्रीमति देवश्री मोदी अध्यक्ष महानगर जबलपुर एवं तुलसी तिवारी प्रांत सह संगठन मंत्री महाकौशल मुख्य रूप से शामिल हुए। उपस्थित अतिथियों का कटरा में पुष्पमाला से स्वागत किया गया और बैठक का आयोजन वनवासी विकास परिषद सक्रिय सदस्य अनिल मिश्रा के आवास में आयोजित की गई। जहां पर उपस्थित अतिथियों का तिलक वंदन करते हुए भगवा वस्त्र से स्वागत किया गया और वनवासी विकास परिषद की रीति नीति के साथ समाजहित में किए जा रहे कामों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आगामी समय पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान परिषद के विस्तार के साथ अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई वहीं विभाग संगठन मंत्री राजू कुडापे ने आयोजित बैठक में सभी का परिचय कराया और वनवासी विकास परिषद द्वारा जिले में किए जा रहे कार्यो से वरिष्ठजनों को अवगत कराया। वहीं बैठक पश्चात अतिथियों ने भोजन कार्यकर्ता शारदा सोनी के यहा ग्रहण किया। बैठक में मुख्य रूप से प्रमोद मरावी प्रांत युवा कार्य सहप्रमुख, किशोरी लाल साहू संरक्षक जिला समिति, जैनकली मरावी जिला महिला प्रमुख, प्रहलाद सिंह धुर्वे जिला संगठन मंत्री, नीरज अग्रवाल जिला मीडिया प्रभारी, कार्यकर्ता सुनीता सैयाम, शीतल वैष्णव, सीता परतेती, अनुराधा मिश्रा, कृष्ण कुमार परते खंड प्रमुख, पवन कुमार धुर्वे खंड प्रमुख मवई मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस बैठक में जिला समिति के पदाधिकारी, पूर्ण कालिक, अंशकालिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

44 विस्थापित परिवारों ने नए आशियाने में रखा कदम

पुनर्वास कॉलोनी में मिलेंगी सभी सुविधाएं

*** प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को मिलेगा रोजगार।**

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला

चुटका परमाणु परियोजना के अंतर्गत प्रभावित परिवारों के सम्मानजनक पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रविवार को ग्राम गौंझीमाल स्थित आर एंड आर (पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन) कॉलोनी में 44 विस्थापित परिवारों का गृह प्रवेश कराया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती सम्पतिया उईके ने नए आवासों में पहुंचकर परिवारों का स्वागत किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर मंत्री श्रीमती उईके ने परिवारों से आत्मीय संवाद करते हुए कहा कि पुनर्वास केवल मकान उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक परिवार को बेहतर जीवन, सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान करना शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने पुनर्वास अवार्ड राशि के प्रतीकात्मक चेक वितरित करते हुए परिवारों को राशि का उपयोग भविष्य के विकास एवं आजीविका सुदृढ़ करने में करने की सलाह दी।

उन्होंने घोषणा की कि पुनर्वास कॉलोनी में धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्था को ध्यान में रखते हुए श्रीराम, हनुमान, राधा-कृष्ण तथा जनजातीय संस्कृति के आराध्य बड़ादेव मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए आगामी दो दिनों के भीतर स्कूल का संचालन प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए गए। मंत्री श्रीमती उईके ने बताया कि परियोजना से प्रभावित प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को आउटसोर्स माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने जानकारी दी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) की चुटका परमाणु परियोजना के तहत कुल 330 परिवार पुनर्वास के दायरे में हैं। इनमें से अब तक 119 परिवारों को गौंझीमाल स्थित आधुनिक पुनर्वास कॉलोनी में बसाया जा चुका है, जबकि शेष परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है।

कार्यक्रम में कलेक्टर श्री राहुल नामदेव धोटे ने विस्थापित परिवारों को आश्वस्त किया कि पुनर्वास के दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नए आवासों में शिफ्ट हुए 44 परिवारों के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक माह तक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी आवश्यक सेवाओं एवं सुविधाओं की नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है।

गौंझीमाल पुनर्वास कॉलोनी को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। यहां स्वच्छ पेयजल, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पक्की सड़कें, सुदृढ़ नाली व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे विस्थापित परिवारों को सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक जीवन मिल सके।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह, एसडीएम मंडला श्रीमती सोनल सिडाम, एसडीएम निवास सी.एल. वर्मा, तहसीलदार हिमांशु भलावी, नायब तहसीलदार श्री अजय श्रीवास्तव, स्थानीय सरपंच विश्राम, एनपीसीआईएल के वरिष्ठ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सरपंच, सचिव के नाम पर लाखों रूपये का भुगतान

*** जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत का अब नहीं रहा नियंत्रण।**

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला

जिले में पंचायतों पर न तो जनपद का अंकुश दिखाई दे रहा है और न ही जिला पंचायत का डर नजर आ रहा है पंचायतों में मनमाने भुगतान और निर्माण कार्यो में गुणवत्ता से समझौता कोई नई बात नहीं है अब तो स्थिति यह आ गई है कि सरपंच, सचिव अपने नाम से सरकारी राशि का आहरण कर रहे हैं। जनपद पंचायत मण्डला की समीपी ग्राम पंचायत पटपरा रैयत में पूर्व महिला सरपंच के नाम पर लाखों का आहरण किया गया है यह जानकारी पंचायत पोर्टल में दर्ज है और यहां वर्षो से पदस्थ सचिव के नाम पर भी 10-10 हजार रूपये का भुगतान कई बार आहरित दिखाया जा रहा है। पंचायत में जो मेट है उसके नाम से भी भुगतान अंकित है स्थानीय चाय वाले के नाम से समय-समय पर हजारों रूपये का भुगतान दर्शाया गया है इसके अलावा ऐसे 100 से ज्यादा नाम है जिनके नाम पर हजारों रूपयों का भुगतान पिछले कुछ वर्षो में किया गया है ये भुगतान किस काम के किये गये हैं और जिनके नाम से भुगतान हुआ है वे क्या वास्तव में है अथवा फर्जी सप्लायर हैं। किसी ग्राम पंचायत में इतने सप्लायर होना भी समझ से परे है बहुत से प्रतिष्ठान ऐसे हैं जिन्हें बार-बार हजारों रूपयों का भुगतान किया गया है यहां तक कि इस ग्राम पंचायत के पोर्टल में सीईओ के नाम से भी भुगतान दर्शाया गया है अब यह भुगतान किस बात के लिये किया गया है यह सार्वजनिक होना चाहिये। स्थानीय लोगों ने पिछले 10-12 वर्षो में जो भी भुगतान किये गये है उनकी गंभीरता से जांच की मांग की है।

इस संबंध में हमनें पंचायत समन्वयक से जब बात की तो उनका कहना था कि साल छः महीने में हम अभिलेखों को सरसरी निगाह से देखते तो हैं अब यदि ऐसे भुगतान हुये हैं तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या मामला है। इस मुद्दे पर जनपद पंचायत मण्डला के कार्यकारी सीईओ से जब पूछा गया तो उन्होंने सरपंच, सचिव के नाम भुगतान को पूर्ण रूप से अवैध बताया उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिये यदि कोई शिकायतकर्ता इसकी शिकायत करेगा तो निश्चित रूप से गंभीरता से जांच की जायेगी।

छिंदवाड़ा -बैतूल हाईवे पर भीषण हादसा : ट्रक ने मजदूरों से भरी पिकअप को मारी टक्कर, 5 की मौत

छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा-बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच मजदूरों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 अन्य मजदूर घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब मजदूरों से भरी एक पिकअप वाहन को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मजदूरों से भरी पिकअप छिंदवाड़ा से बैतूल की ओर जा रही थी। वाहन में बड़ी संख्या में मजदूर सवार थे, जो रोजगार के सिलसिले में यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान हाईवे पर तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने पिकअप को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार मजदूर सड़क पर जा गिरे।

हादसे में पांच मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग 20 लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं। स्थानीय लोगों ने भी राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग किया और घायलों को वाहन से बाहर निकालने में मदद की।

सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। गंभीर रूप से घायल कुछ मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। चिकित्सकों की टीम लगातार घायलों की निगरानी कर रही है।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की रफ्तार काफी अधिक थी और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। हालांकि पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ट्रक चालक की तलाश की जा रही है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है।

घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। कई परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि मृतकों में अधिकांश मजदूर अपने परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य थे। अस्पताल में परिजनों और रिश्तेदारों की भीड़ जुटी रही।

प्रशासनिक अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और उपचार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों को हरसंभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है।

यह हादसा एक बार फिर मजदूरों के असुरक्षित परिवहन और हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों के खतरे को उजागर करता है। आए दिन होने वाली ऐसी दुर्घटनाएं सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से हाईवे पर यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने और मजदूरों के सुरक्षित परिवहन के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया जारी है। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है।

उरधन खुली खदान ने रचा नया कीर्तिमान, बिना कोयला स्टॉक में आग लगे हुआ शत-प्रतिशत उत्पादन एवं डिस्पैच

छिंदवाड़ा। उरधन खुली खदान (**OCM**) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए शत-प्रतिशत कोयला उत्पादन एवं डिस्पैच का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा किया। विशेष बात यह रही कि पूरे वर्ष के दौरान कोयला स्टॉक में आग लगने की कोई घटना नहीं हुई और सुरक्षित रूप से कोयले का डिस्पैच किया गया।

इस सफलता के पीछे उरधन खदान के माइन मैनेजर **Sandeep Washington** एवं उनकी पूरी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गत वर्ष स्थानांतरित होकर आए श्री वाशिंगटन ने अपने अनुभव, कुशल प्रबंधन एवं प्रभावी निगरानी के माध्यम से कोयला स्टॉक में आग लगने जैसी गंभीर समस्या पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया।

गौरतलब है कि उरधन क्षेत्र में पूर्व वर्षों में कोयला स्टॉक में आग लगने की घटनाएं होती रही हैं, जिससे कंपनी को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। कोयला खदानों एवं स्टॉकों में आग लगना उद्योग के लिए एक गंभीर चुनौती माना जाता है और इससे उत्पादन व संसाधनों को नुकसान पहुंच सकता है। इस उपलब्धि में क्षेत्र के महाप्रबंधक (जीएम) का मार्गदर्शन एवं सहयोग भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उनके नेतृत्व में खदान प्रबंधन ने सुरक्षा, उत्पादन एवं डिस्पैच व्यवस्था को बेहतर बनाते हुए उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए।

उरधन क्षेत्र की जनता, श्रमिकों एवं विभिन्न श्रमिक संगठनों ने इस सराहनीय कार्य के लिए माइन मैनेजर श्री संदीप वाशिंगटन, उनकी टीम तथा क्षेत्रीय प्रबंधन को बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापित किया है। सभी ने आशा व्यक्त की है कि भविष्य में भी इसी प्रकार सुरक्षित एवं उत्कृष्ट कार्य संस्कृति के माध्यम से खदान नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी।

राजस्व स्टांप के नाम पर खुली लूट! छिंदवाड़ा में 100 का स्टांप 150 तक बिकने के आरोप, जनता पूछ रही—कब रुकेगा यह खेल?

छिंदवाड़ा। जिले में राजस्व स्टांप की बिक्री को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आम नागरिकों, किसानों, मजदूरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से लगातार ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं कि निर्धारित मूल्य ₹100 वाले राजस्व स्टांप के लिए उनसे ₹130 से ₹150 तक वसूले जा रहे हैं। आरोप है कि स्टांप विक्रेताओं द्वारा कृत्रिम कमी का माहौल बनाकर मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं, जबकि प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है।

जिले के कई तहसील मुख्यालयों, उप पंजीयक कार्यालयों और स्टांप विक्रय केंद्रों पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग शपथ पत्र, अनुबंध, बैंकिंग कार्य, भूमि संबंधी दस्तावेज और अन्य सरकारी औपचारिकताओं के लिए राजस्व स्टांप खरीदने पहुंचते हैं। लेकिन जरूरतमंद नागरिकों का आरोप है कि निर्धारित मूल्य पर स्टांप उपलब्ध नहीं कराए जा रहे और अतिरिक्त राशि देने पर ही स्टांप मिल पाते हैं।

कृत्रिम कमी बनाकर वसूली का आरोप

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई स्थानों पर स्टांप उपलब्ध होने के बावजूद कमी का हवाला दिया जाता है। इसके बाद जरूरतमंद लोगों को अधिक कीमत पर स्टांप बेच दिए जाते हैं। खास बात यह है कि अधिकांश लोग अपने जरूरी कामों के कारण मजबूरी में अधिक भुगतान कर देते हैं, क्योंकि उन्हें उसी दिन दस्तावेजी कार्य पूरा करना होता है।

ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले किसानों और मजदूरों का कहना है कि उन्हें पहले से ही यात्रा, टाइपिंग, नोटरी और अन्य खर्चों का बोझ उठाना पड़ता है। ऐसे में यदि ₹100 के स्टांप के लिए ₹150 तक चुकाने पड़ें तो उनकी जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है।

सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब और ग्रामीण वर्ग

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कथित अनियमितता का सबसे ज्यादा असर गरीब, किसान, मजदूर और ग्रामीण नागरिकों पर पड़ता है। शहर के जागरूक लोग तो शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन गांवों से आने वाले अधिकांश लोग व्यवस्था के सामने खुद को असहाय महसूस करते हैं।

कई लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, जिसके कारण ऐसे तत्वों के हौसले बुलंद बने रहते हैं। यही वजह है कि वर्षों से यह समस्या समय-समय पर सामने आती रही है।

प्रशासनिक निगरानी पर उठ रहे सवाल

यदि वास्तव में निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूली जा रही है तो यह सवाल भी उठना स्वाभाविक है कि संबंधित विभाग और प्रशासनिक अधिकारी इसकी निगरानी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। राजस्व स्टांप की बिक्री एक नियंत्रित व्यवस्था के तहत होती है, ऐसे में खुलेआम अधिक मूल्य वसूले जाने के आरोप गंभीर जांच का विषय हैं।

जनता पूछ रही है कि—क्या स्टांप की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है? यदि स्टांप उपलब्ध हैं तो अधिक कीमत क्यों ली जा रही है? शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?क्या जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जा रहा है?

क्या दोषी पाए जाने वालों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे?

करोड़ों के कारोबार पर निगाह जरूरी

जानकारों का कहना है कि राजस्व स्टांप और दस्तावेजी कार्यों का कारोबार करोड़ों रुपये का है। यदि छोटे-छोटे स्तर पर भी निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूली जा रही है, तो लंबे समय में यह रकम काफी बड़ी हो सकती है। इसलिए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है ताकि वास्तविक स्थिति जनता के सामने आ सके।

जनता की मांग—हो निष्पक्ष जांच

छिंदवाड़ा जिले के नागरिकों ने मांग की है कि जिला प्रशासन, कलेक्टर और संबंधित राजस्व विभाग इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएं। स्टांप विक्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जाए, निर्धारित मूल्य सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कराई जाए और यदि कहीं अधिक राशि वसूली जा रही हो तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

बड़ा सवाल

आज छिंदवाड़ा की जनता जानना चाहती है कि क्या ₹100 का राजस्व स्टांप वास्तव में ₹100 में उपलब्ध होगा या फिर आम नागरिकों को इसी तरह अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ेगी? क्या प्रशासन इस कथित लूट पर लगाम लगाएगा? क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी?

फिलहाल यह मुद्दा आमजन की जेब से जुड़ा हुआ है और लोग प्रशासन से केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं। छिंदवाड़ा पूछ रहा है—राजस्व स्टांप के नाम पर हो रही इस कथित लूट पर आखिर कब लगेगी रोक?

रेत माफियाओं के आगे बेबस प्रशासन! दिन-दहाड़े हो रहा अवैध उत्खनन, जिम्मेदारों की चुप्पी पर उठे सवाल

छिंदवाड़ा। जिले में अवैध रेत उत्खनन का कारोबार एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। नदियों और घाटों से दिन-दहाड़े भारी मशीनों और वाहनों के माध्यम से रेत निकाली जा रही है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि अवैध उत्खनन का यह खेल लंबे समय से चल रहा है और शिकायतों के बावजूद कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रह जाती है। अवैध खनन के कारण नदियों का स्वरूप बदल रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और शासन को करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है।

जानकारों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में खनन की अनुमति नहीं है, वहां भी खुलेआम रेत निकाली जा रही है। कई स्थानों पर रात के बजाय अब दिन में भी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और डंपर बेखौफ दौड़ते देखे जा सकते हैं। इससे यह सवाल उठ रहा है कि आखिर रेत माफियाओं को किसका संरक्षण प्राप्त है कि वे प्रशासनिक कार्रवाई के भय के बिना काम कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नदी तटों पर लगातार हो रहे उत्खनन से जलस्तर प्रभावित हो रहा है। बरसात के मौसम में कटाव बढ़ने की आशंका है और कई स्थानों पर खेतों तथा ग्रामीण मार्गों को भी नुकसान पहुंच रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञ भी लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि अनियंत्रित रेत खनन से नदियों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, जिससे भविष्य में जल संकट और गंभीर हो सकता है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रशासन के पास राजस्व, खनिज, पुलिस और स्थानीय निकायों का पूरा अमला मौजूद है, तब भी अवैध उत्खनन पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति हुई। कुछ वाहनों की जब्ती और मामूली जुर्माने के बाद पूरा कारोबार फिर पहले की तरह शुरू हो जाता है। इससे माफियाओं के हौसले और बुलंद हो रहे हैं।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में समय-समय पर अवैध रेत खनन को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। कई मामलों में प्रशासन को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करनी पड़ी है, जबकि कहीं-कहीं अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमले तक हुए हैं। यह दर्शाता है कि अवैध खनन केवल राजस्व हानि का मामला नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और पर्यावरण सुरक्षा से भी जुड़ा गंभीर विषय है।

छिंदवाड़ा जिले में भी पहले अवैध रेत भंडारण और उत्खनन को लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा विरोध दर्ज कराया जा चुका है। आरोप लगाए गए थे कि रेत का अवैध भंडारण सार्वजनिक स्थलों तक में किया जा रहा है और संबंधित विभाग मूकदर्शक बना हुआ है। ऐसे मामलों के बाद भी यदि स्थिति में सुधार नहीं आता, तो यह प्रशासनिक इच्छाशक्ति पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन चाहे तो अवैध उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। जिले की सीमाओं पर चेकपोस्ट, नियमित निरीक्षण, ड्रोन निगरानी और संयुक्त कार्रवाई के माध्यम से इस अवैध कारोबार को काफी हद तक रोका जा सकता है। प्रदेश के अन्य जिलों में बड़े स्तर पर छापेमारी कर दर्जनों वाहन जब्त किए जाने के उदाहरण भी सामने आ चुके हैं।

अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेंगे या फिर रेत माफियाओं का यह खेल यूं ही चलता रहेगा? आखिर कब तक नदियों की छाती छलनी होती रहेगी और शासन को राजस्व का नुकसान होता रहेगा? जनता जवाब चाहती है कि दिन-दहाड़े हो रहे इस अवैध उत्खनन के पीछे कौन लोग हैं और उन पर कार्रवाई कब होगी?

रेत माफियाओं के बढ़ते हौसलों और प्रशासनिक निष्क्रियता के बीच आम लोगों की निगाहें अब जिला प्रशासन और खनिज विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले दिनों में यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है।

कृषि विस्तार अधिकारी ने किया खेतों का भ्रमण

हरिभूमि न्यूज वारासिवनी। कृषि विस्तार अधिकारी डी के खंडेलकर द्वारा अपने आश्रित क्षेत्रों ग्राम डोरली, सेरपार, गटापायली, कोचेवाही का भ्रमण किया।

इस दौरान उन्होंने कृषको को खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। ग्राम डोरली में कृषकश्री रिमसिंह परते प्रगतिशील कृषक के खेत मे जाकर स्टेप सीडर जो किसान ने अपने खेती के क्रय किया है, उसके क्या फायदे है, इस पर प्रकाश डालते हुए उन्हें स्टेप सीडर की जानकारी दी गई। कृषकों को आज की श्रमिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए ₹ कृषको को DSR के माध्यम से धान की बुवाई करना आवश्यक है, जिसमे कृषक स्टेप सीडर या सुपर सीडर का प्रयोग करके अपनी लागत को कम कर सकता है।स्टेप सीडर से कृषक को पानी की समस्या नही आएगी, इससे किसान को समय की बचत होगी, कृषक को बीज, खाद, कम लगेगा, कृषक को कम लागत में अधिक उत्पादन मिलेगा, कृषक उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करे, बीज उपचार करके बोए, खेत की तैयारी कर हरी खाद का प्रयोग करे, जैसे सन, ढेंचा, मूंग उरद, इत्यादि जानकारी दी गई। ग्राम डोरली में कृषकों को चौपाल के माध्यम से खेती किसानी की जानकारी देते हुए संतुलित खाद डालने हेतु सलाह दी गई।

ग्राम सेरपार में श्रीकृषक जितेंद्र राहंगडाले के खेत मे लगभग 3,-4 एकड़ में सुपर सीडर से बोनी की गई है कृषक को मार्गदर्शन दिया गया कि सुपर सीडर से आपकी मजदूर की समस्या दूर होगी एवं कम लागत में अधिक उत्पादन होगा। कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा समय समय पर कृषको को उचित सलाह जानकारी दिया जाता रहा है । ग्राम कोचेवाही में चौपाल के माध्यम से समिति के माध्यम से कृषकों को उचित मार्गदर्शन दिया गया, कृषकों को टोकन प्रणाली से खाद की जानकारी दी गई, कृषि विभाग के माध्यम से उन्नत बीज अरहर , धान एवं राम तिल के बीज की जानकारी दी गई। कृषक अपनी भूमि की तैयारी के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग, खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडमेथलीन दवाई का स्प्रे कर खरपतवार की रोकथाम कर सकते है। अन्त में सामूहिक चर्चा कर कृषकों को समय समय पर

महिलाओं की शिकायत पर हुई कार्रवाई, नहीं हटाया तो प्रशासन करेगा कार्रवाई

सेलवा में पटवारियों ने अवैध दुकानों को 2 दिन में हटाने की चेतावनी

हरिभूमि न्यूज कटंगी।

तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत सेलवा के डोंगरूटोला में सड़क की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त हो गया है। देसी-विदेशी शराब दुकान के सामने बनी अवैध दुकानों को हटाने के लिए पटवारियों ने अतिक्रमणकारियों को दो दिन का अल्टीमेटम दिया है। ग्राम सेलवा की महिलाओं ने एसडीएम और तहसील कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में महिलाओं ने बताया कि डोंगरूटोला में संचालित शराब दुकान के सामने सड़क की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से दुकानें बना ली हैं। महिलाओं का आरोप था कि इन दुकानों में पहले अवैध तरीके से शराब परोसी जाती थी। फिलहाल ये दुकानें बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद इन अवैध दुकानों में शराबी लोग बैठे रहते हैं, जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है। महिलाओं की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम और तहसीलदार ने पटवारियों को मौका निरीक्षण के लिए भेजा। 22 जून की शाम 05 बजे पटवारियों की टीम सेलवा पहुंची और डोंगरूटोला स्थित शराब दुकान के सामने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शराब दुकान के सामने सड़क की शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से दुकानें बनाकर अतिक्रमण किया गया है। मौके पर मौजूद पटवारियों ने अतिक्रमणकारियों को बुलाकर सख्त लहजे में चेतावनी दी। पटवारियों ने साफ कहा कि यह शासकीय भूमि है और इस पर किया गया अतिक्रमण अवैध है। अतिक्रमणकारियों को स्वेच्छा से दो दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। चेतावनी के बाद अतिक्रमणकारियों ने पटवारियों को दो दिनों के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटा लेने का भरोसा दिया है। पटवारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन द्वारा बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी और अतिक्रमण हटाने का खर्च भी अतिक्रमणकारियों से ही वसूला जाएगा। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई पर ग्राम सेलवा की महिलाओं ने संतोष जताया है।

जनपद सदस्य अजीत बिसेन ने समझा ग्रामीणों का दर्द, बड़ा टोला में दूर हुआ पेयजल संकट

हरिभूमि न्यूज कटंगी। भीषण गर्मी में पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों की समस्या को जनपद सदस्य अजीत बिसेन ने गंभीरता से लिया। जनपद पंचायत कटंगी की ग्राम पंचायत आगरवाड़ा के बड़ा टोला में ग्रामीण लंबे समय से पीने के पानी के लिए परेशान थे। ग्रामीणों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए जनपद सदस्य ने अपनी जनपद निधि से सबमर्सिबल पंप प्रदान किया। विगत दिवस जनपद सदस्य अजीत बिसेन सरपंच डॉ. कमलेश राहंगडाले के साथ बड़ा टोला पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की मौजूदगी में टोले के एक सरकारी बोरवेल में सबमर्सिबल पंप लगवाया। पंप लगते ही बोरवेल से पानी की धार शुरू हो गई और ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। जैसे ही ग्रामीणों को पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हुआ, ग्रामीण गणेश चौधरी, फूलचंद पारधी, रमेश राउत, दिलीप राउत, बंडु बिसेन, दीपक शेंडे सहित अन्य परिवारों ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ ही टोले के हैंडपंप और कुएं सूख गए थे। महिलाओं को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता था। जनपद सदस्य अजीत बिसेन ने कहा, बड़ा टोला के लोगों ने पेयजल की समस्या बताई थी। गर्मी में पानी की किल्लत सबसे बड़ी समस्या होती है। जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा फर्ज था कि ग्रामीणों की परेशानी दूर करूं। जनपद निधि जनता के लिए ही है। आगे भी जहां जरूरत होगी, मदद करेंगे। सरपंच डॉ. कमलेश राहंगडाले ने कहा कि पंचायत स्तर पर भी समस्या के समाधान का प्रयास किया जा रहा था। जनपद सदस्य ने तत्परता दिखाई और पंप उपलब्ध कराया, इसके लिए हम आभारी हैं। अब टोले के परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

जन अभियान परिषद द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय किरनापुर में योगाशन कराया गया

हरिभूमि न्यूज किरनापुर। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड किरनापुर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेक्टर क्रमांक 01 कार्यक्रम स्थल उत्कर्ष विद्यालय ग्राउंड किरनापुर सभी विभाग संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी गणेश सोनी जी योग प्रशिक्षक श्री दुर्गा प्रसाद राहगडालेजी विजय बोपचे ,श्रीमती कल्पना राहगडाले स्वास्थ्य विभाग किरनापुर समस्त शिक्षा विभाग बाल विकास अधिकारी गण, एवं एनसीसी के छात्र ,पंचायत किरनापुर अधिकारी आशा कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समाज सेवीवरिष्ठ नगरीकरण सम्मिलित श्री गणेश सोनी जी शिक्षा विभाग अधिकारी योग से संबधित अपने विचार रखा। श्री दुर्गा प्रसाद रहगडाले जी बहुत अच्छा योग करवायें प्रैक्टिकल करते हुए योग का महत्व समझाया। इस प्रकार क्षेत्रीय सहयोग ग्राम विकास संस्था के संचालक बी सी मंडलवार जी ने गौ आधारित जैविक खेती पर अपने विचार रखकर उनका महत्व समझाया गया। एवं अन्य स्वस्थ परिवार के संबंधित जानकारी प्रदान की गई। पर्यावरण का महत्व समझाते हुए योग दिवस की शुभ अवसर पर सभी वरिष्ठ नगरीकरण समस्त पदाधिकारी सभी को योगाभ्यास का एवं योग करने की प्रेरणा दी गई । जिला जन अभियान परिषद के समन्वयक अधिकारी महेश पटले, व ब्लॉक समन्वयक श्रीमती रुचिका वैध शामिल हुई।

सीबीएसई अकादमिक संस्थान बिसोनी में शिक्षकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न

NEP 2020, हैप्पी क्लासरूम और AI इन एजुकेशन पर हुआ मंथन, शिक्षकों को मिले नवाचार आधारित शिक्षण के गुर

हरिभूमि न्यूज लांजी। जिले के लांजी क्षेत्र के सीबीएसई अकादमिक संस्थान बिसोनी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शिक्षकों के लिए दो दिवसीय इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को नई शिक्षा नीति 2020, हैप्पी क्लासरूम और शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे समकालीन विषयों से जोड़ना रहा। कार्यक्रम में शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर आधुनिक शिक्षण पद्धतियों की जानकारी प्राप्त की।कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान प्रमुख श्रीमती वंदना वैद्य, प्राचार्य श्रीमती श्रद्धा कांड्रा, प्रबंधक संजय चौरे तथा रिसोर्स पर्सन हरिओम दुबे एवं कमलकांत विठले द्वारा दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती पूजन के साथ किया गया।

कार्यशाला के प्रथम सत्र में रिसोर्स पर्सन हरिओम दुबे ने "हैप्पी क्लासरूम" की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि एक खुशहाल शिक्षक ही सकारात्मक और आनंदमय कक्षा का निर्माण कर सकता है। सत्र में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आत्म-नियंत्रण और शिक्षक-छात्र संबंधों को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। विभिन्न गतिविधियों, समूह चर्चा और केस स्टडी के माध्यम से शिक्षकों को बताया गया कि कक्षा के तनाव को कम कर पढ़ाई को अधिक रोचक, प्रभावी और आनंददायक कैसे बनाया जा सकता है। इस सत्र ने शिक्षकों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से नई सीख प्रदान की।

दूसरे सत्र में कमलकांत विठले ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के व्यावहारिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने शिक्षकों को पारंपरिक रटने की प्रवृत्ति से आगे बढ़कर गतिविधि-आधारित शिक्षण और अनुभवात्मक शिक्षण अपनाने के लिए प्रेरित किया।उन्होंने छात्र-केंद्रित शिक्षण वातावरण तैयार करने और बच्चों के समग्र विकास के लिए नई शिक्षण पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। AI आधारित शिक्षा के महत्व पर भी चर्चा हुई, जिससे शिक्षकों को तकनीक के बेहतर उपयोग की जानकारी मिली।

केशव विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस गरिमामय वातावरण में संपन्न

हरिभूमि न्यूज वारासिवनी।

केशव इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल वारासिवनी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अत्यंत उत्साह, अनुशासन एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। प्रातःकालीन पावन बेला में विद्यालय प्रांगण योगमय वातावरण से आलोकित हो उठा, जहाँ विद्यार्थियों, शिक्षकगणों एवं नगर के गणमान्य नागरिकों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास कर स्वस्थ, संतुलित एवं संस्कारित जीवन का संदेश दिया।

कार्यक्रम में ज्ञान विकास समिति अध्यक्ष प्रदीप तिवारी, सचिव विजय तेलास्कर, स्कूल सुपरिंटेंडेंट जितेंद्र टेंभरे, विद्यालय प्राचार्य मयंक मिश्रा, समस्त शिक्षकगण, विद्यार्थीगण एवं नगर के गणमान्य नागरिक विशेष रूप से उपस्थित रहे।इस अवसर पर उपस्थित सभी जनों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास किया। कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, अपितु भारतीय संस्कृति की वह अमूल्य धरोहर है, जो शरीर को स्वास्थ्य, मन को शांति, बुद्धि को एकाग्रता और जीवन को अनुशासन प्रदान करती है।विद्यालय के सचिव विजय तेलास्कर ने अपने उद्बोधन में कहा कि योग भारतीय चिंतन, परंपरा एवं जीवन दर्शन का अभिन्न अंग है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए योग अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह उनमें एकाग्रता, आत्म विश्वास, अनुशासन एवं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। उन्होंने विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं उपस्थित नागरिकों से आह्वान किया कि योग को केवल एक दिवस का कार्यक्रम न मानकर दैनिक जीवन की नियमित साधना बनाया जाए।कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों ने भी योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज सम्पूर्ण विश्व योग के माध्यम से भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को स्वीकार कर रहा है। योग मानवता को स्वास्थ्य, सद्भाव, संयम और आत्मिक शांति का मार्ग दिखाता है।अंत में विद्यालय परिवार द्वारा सभी उपस्थित नागरिकों, विद्यार्थियों एवं शिक्षकगणों को नियमित योगाभ्यास करने तथा स्वस्थ एवं अनुशासित जीवन जीने का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम विद्यालय परिवार के सामूहिक सहयोग, अनुशासन एवं उत्साहपूर्ण सहभागिता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

खबर संक्षेप

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत कामाख्या तीर्थ यात्रा हेतु आवेदन आमंत्रित

हरिभूमि न्यूज सिवनी। मध्यप्रदेश शासन की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत कामाख्या तीर्थ यात्रा के लिए सिवनी जिले को कुल 196 यात्रियों का कोटा आवंटित किया गया है। यह यात्रा 11 जुलाई 2026 से 16 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाएगी।

जिला प्रशासन द्वारा जिले के पात्र वरिष्ठ नागरिकों एवं इच्छुक श्रद्धालुओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक अपने आवेदन जनपद पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, नगरपालिका अथवा नगर परिषद कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 जून 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन के साथ आयु संबंधी प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी अथवा अन्य वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र) तथा समग्र आईडी की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

जिला प्रशासन ने पात्र नागरिकों से निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने का आग्रह किया है, ताकि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र श्रद्धालु कामाख्या तीर्थ यात्रा का लाभ प्राप्त कर सकें। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आवेदक अपने निकटतम जनपद पंचायत, तहसील, नगरपालिका अथवा नगर परिषद कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

नशामुक्त भारत सप्ताह के अंतर्गत जिलेभर में जनजागरूकता अभियान जारी

हरिभूमि न्यूज सिवनी। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निर्देशानुसार जिले में नशामुक्त भारत सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य आमजन, विशेषकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना है। इसी क्रम में जिलेभर में प्रचार वाहन के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। प्रचार वाहन द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भ्रमण कर नशे के दुष्परिणामों, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों तथा नशामुक्त जीवनशैली अपनाने के संबंध में संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। अभियान के तहत नागरिकों को नशे से दूर रहने, परिवार एवं समाज को नशामुक्त बनाने तथा युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न विभागों के समन्वय से शपथ कार्यक्रम, जागरूकता रैलियां, संवाद सत्र एवं अन्य गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे नशामुक्त भारत अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए स्वयं नशे से दूर रहें तथा अपने आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें।

प्राचार्य पर दुर्व्यवहार का आरोप, कलेक्टर से निलंबन एवं जांच की मांग

सिवनी। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी के प्राचार्य के खिलाफ छात्र हितों की अनदेखी एवं अभद्र व्यवहार के आरोप लगाते हुए कलेक्टर सिवनी को शिकायत सौंपकर तत्काल निलंबन और विभागीय जांच की मांग की गई है।

शिकायतकर्ता युवक

शिकायतकर्ता दीपक डेहरिया (दीपक जयहिंद), अध्यक्ष, दीपक जयहिंद टीम सिवनी ने आवेदन में बताया कि वे 22 जून 2026 को कुछ विद्यार्थियों के कक्षा 11वीं कृषि संकाय में प्रवेश संबंधी समस्या को लेकर विद्यालय पहुंचे थे। उनका आरोप है कि प्राचार्य ने उनकी बात सुनने के बजाय उनके साथ अभद्र, अपमानजनक एवं असम्मानजनक व्यवहार किया तथा कार्यालय से बाहर जाने के लिए कहा। साथ ही कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि उन्हें विद्यालय परिसर और कार्यालय में प्रवेश न करने दिया जाए। आवेदन में कहा गया है कि वे विद्यार्थियों के हित एवं प्रवेश संबंधी समस्या के समाधान के लिए शांतिपूर्ण और वैधानिक रूप से चर्चा करने पहुंचे थे। शिकायत के अनुसार, प्राचार्य का यह व्यवहार एक सार्वजनिक संस्था के प्रमुख के अनुरूप नहीं है और इससे विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में भय और असंतोष का वातावरण बना है।

शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा जांच पूरी होने तक प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, ताकि जांच प्रभावित न हो। साथ ही यदि आरोप सत्य पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। विद्यार्थियों के प्रवेश प्रकरण का भी शीघ्र, मानवीय एवं न्यायोचित आधार पर निराकरण करने की मांग की गई है। फिलहाल मामले में विद्यालय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शिकायत की जांच के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी।

समय पर नहीं उठा राशन तो अन्नदूत परिवहनकर्ताओं पर होगी सख्त कार्रवाई

30 जून तक जुलाई माह का खाद्यान्न उठाने का लक्ष्य

हरिभूमि न्यूज ⏭ सिवनी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत शासकीय राशन का समय-सीमा में उठाव सुनिश्चित करने के लिए खाद्य विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला आपूर्ति अधिकारी देवेंद्र कुमार खोबरिया की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के परिवहनकर्ताओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी माह जुलाई 2026 के खाद्यान्न का उठाव 30 जून 2026 तक हर हाल में पूर्ण कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि तय समय-सीमा में कार्य पूर्ण न करने वाले परिवहनकर्ताओं के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में निर्देशित किया गया कि पीडीएस के साथ-साथ मध्यान्ह भोजन एमडीएम एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस और कल्याणकारी संस्थाओं केकेवाय राशन का उठाव भी समय-सीमा में करना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जिले के सभी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों, केएमपीएससीएससी प्रदाय केंद्र प्रभारियों एमपीडॅब्लू एलसी और के शाखा प्रबंधकों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित रूप से गोदाम खुलवाकर नियमानुसार उठाव पूर्ण कराएं।

इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला सिवनी द्वारा आदेश क्रमांक/खाद्य-पीडीएस/ 714/2026 जारी कर दिया गया है।

नगर पालिका परिषद सिवनी में बैठकों के अभाव पर कांग्रेस पार्षद दल ने उठाए सवाल

हरिभूमि न्यूज ⏭ सिवनी।

नगर पालिका परिषद सिवनी में लगातार नियमों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्षद दल ने कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोदिया के खिलाफ मोर्चा खोला है। पार्षदों का आरोप है कि नगर पालिका की अध्यक्षीय परिषद (पीआईसी) की बैठक पिछले लगभग 16 माह से आयोजित नहीं की गई है, जबकि परिषद की सामान्य बैठक भी पिछले चार माह से नहीं हुई है।

कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि नगर पालिका अधिनियम के अनुसार पीआईसी की बैठक प्रत्येक माह तथा परिषद की बैठक प्रत्येक दो माह में आयोजित किया जाना अनिवार्य है। बैठकों के नियमित आयोजन नहीं होने से नगर विकास से जुड़े अनेक प्रस्ताव लंबित पड़े हैं और विभिन्न विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका कार्यालय में आम नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कई विभागों में कर्मचारी उपलब्ध नहीं रहते, तो कहीं पोर्टल बंद होने के कारण कार्य बाधित हो रहे हैं। उनका कहना है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए परिषद की बैठक आवश्यक है, लेकिन बैठक नहीं होने से जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है।

कांग्रेस पार्षद दल ने इसे कार्यकारी अध्यक्ष का तानाशाही रवैया बताते हुए भाजपा की आंतरिक गुटबाजी से भी जोड़कर देखा है। उनका आरोप है कि राज्य शासन द्वारा कुछ माह पूर्व नियुक्त किए गए एल्डरमैनों में कार्यकारी अध्यक्ष के समर्थक शामिल नहीं हैं, जिसके कारण परिषद की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है। सामान्यतः परिषद की बैठक में एल्डरमैनों का स्वागत एवं निर्वाचित पार्षदों, अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय कराया जाता है। पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी बैठक कराने के पक्ष में सक्रिय दिखाई नहीं दिए। इस संबंध में पूर्व कलेक्टरों को भी शिकायतें की गईं, लेकिन न तो कोई लिखित जवाब मिला और न ही परिषद की बैठक आयोजित कराई गई।

कांग्रेस पार्षद दल ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर नगर पालिका अधिनियम के अनुसार नियमित बैठकों का आयोजन सुनिश्चित कराने की मांग की है। वहीं नगर पालिका प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी है।

देर रात तेज आवाज में डीजे बजाने पर कोतवाली पुलिस की कार्रवाई

साउंड सिस्टम सहित पिकअप वाहन जब्त

हरिभूमि न्यूज ⏭ सिवनी।

पुलिस ने अवैध रूप से और निर्धारित समय सीमा के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ सख्त रूख अपनाते हुए कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस ने देर रात तेज आवाज में डीजे बजाकर कोलाहल करने वाले एक संचालक पर मामला दर्ज कर डीजे साउंड सिस्टम व एक पिकअप वाहन जब्त कर लिया है।

पुलिस के अनुसार 20 जून को ज्यारत नाका के सितारा पैलेस के पास अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाने की मुखबिर से मिली सूचना मिली थी, जिससे आसपास के रहवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां पाया कि डीजे संचालक द्वारा बिना किसी वैध अनुमति, निर्धारित समय सीमा के बाद भी तेज आवाज में फिल्मी गाने बजाकर कोलाहल उत्पन्न किया जा रहा था।

पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम सुभाष वार्ड निवासी विजय उर्फ विक्की पुत्र महेश सोनी (40) बताया। डीजे बजाने की वैध अनुमति न होने और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की शर्तों का खुलेआम उल्लंघन करने पर पुलिस ने आरोपित संचालक के विरुद्ध धारा 7/15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है। मौके से पुलिस ने पिकअप वाहन (क्रमांक एमपी 22 जी 3748) सहित संपूर्ण डीजे साउंड सिस्टम जब्त किया है, जिसमें 4 बेस, 2 टाप, 1 मिक्सर क्रास ओवर, 1 जनरेटर, 4 पार लाइट और 1 लाइट मिक्सर शामिल है। कार्रवाई में कोतवाली स्टाफ शामिल रहा। सिवनी पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे, लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि यंत्रों का प्रयोग बिल्कुल न करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी इसी तरह सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

बोवनी के दौरान रोटावेटर की चपेट में आए 18 वर्षीय युवक की मौत

हरिभूमि न्यूज सिवनी। जिले के केवलारी थाना अंतर्गत अलोनी खापा में 21 जून की शाम एक बेहद हृदयविदारक घटना सामने आई है। खेत में धान की बोवनी के दौरान एक 18 वर्षीय युवक ट्रैक्टर में लगे रोटावेटर की चपेट में आ गया, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस वीभत्स घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है।

पुलिस के अनुसार केवलारी से बगलई मार्ग पर लगभग 17-18 किलोमीटर दूर अलोनी खापा गांव में शाम लगभग 4 बजे के बीच हुआ। बताया जा रहा है कि गांव के ही सौरभ पटेल के खेत में धान की बुवाई का कार्य चल रहा था। ट्रैक्टर में रोटावेटर चल रहा था और पीछे की तरफ सीड ड्रिल (सिडल) मशीन लगी हुई थी। मृतक युवक की पहचान सोनू पुत्र नेहरू दास (18) अलोनी खापा के रूप में हुई है, खेत में बोवनी के काम में मजदूरी करने गया था। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, हादसा उस वक्त हुआ जब सोनू संभवतः मशीन के पीछे यह देखने झुका कि सीड ड्रिल से बीज सही तरीके से गिर रहा है या नहीं। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और वह फिसलकर सीधे रोटावेटर की तेज ब्लेड्स की चपेट में आ गया। रोटावेटर की चपेट में आने के कारण युवक का सिर कटकर धड़ से अलग हो गया और इंजन की तरफ जा गिरा, जिससे उसकी तत्काल ही मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही डायल 100/112 तथा केवलारी पुलिस बकी टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर पहुंचे पुलिस वाहन के पायलट शंकर देशमुख व उनके साथ मौजूद सैनिक बलराम उदाली के अलावा केवलारी पुलिस बल ने पंचनामा कार्रवाई के बाद मर्ग कायम कर शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले में आगे जांच कर रही है।

शक्ति वाहिनी जनसंपर्क अभियान का आयोजन, ग्रामीण महिलाओं को डाकघर योजनाओं की दी गई जानकारी

सोनखार । ग्राम पंचायत सोनखार में 19 जून 2026 को India Post के पोस्ट ऑफिस सोनखार द्वारा "शक्ति वाहिनी जनसंपर्क अभियान" के अंतर्गत एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, विशेषकर महिलाओं को डाकघर की बचत एवं बीमा योजनाओं के प्रति जागरूक करना था। शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को पोस्ट ऑफिस की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे SSA (सुकन्या समृद्धि खाता), RD (Recurring Deposit), SB (Saving Account), TD (Time Deposit) एवं जीवन बीमा योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि डाकघर की ये योजनाएं सुरक्षित बचत के साथ-साथ भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहायक हैं।

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण महिलाओं एवं परिवारों को नियमित बचत करने, अपनी बेटियों के भविष्य के लिए निवेश करने तथा बीमा योजनाओं से जुड़कर अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में उपस्थित लोगों ने योजनाओं में गहरी रुचि दिखाई और कई लोगों ने मौके पर ही जानकारी प्राप्त कर योजना से जुड़ने की इच्छा जताई। पोस्ट ऑफिस सोनखार की टीम ने सभी ग्रामीणों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में डाकघर की योजनाओं का लाभ उठाएं तथा अपने परिवार और समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं।

सड़क दुर्घटना मे युवक की मौत

सिवनी। विकासखंड केवलारी के अंतर्गत ग्राम पंचायत लोपा निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति की सडक दुर्घटना में सोमवार को सुबह लगभग 11.30 बजे मृत्यु हो गई। युवक बाइक से अकेले कहीं जा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दू परिषद के किसान परिषद् के सिवनी जिला अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर पिता प्रहलाद ठाकुर उम्र 40 सोमवार को सुबह वे अपने गांव लोपा से सिवनी दिशा की ओर किसी काम से निकले थे। उनकी बाइक जब मुनगापार के समीप पहुंची तभी दूध वाले किसी बड़े वाहन चालक ने टक्कर मार दिया जिससे घटनास्थल पर ही प्रकाश ठाकुर की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि प्रकाश ठाकुर के दो मासूम बच्चे हैं। एक 7 साल का व एक 5 साल का बेटा है। सडक दुर्घटना में युवक की मौत से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

लखनादौन जन कल्याण शिविर में 9029 आवेदन हुए प्राप्त, 8450 का हुआ निराकरण

हरिभूमि न्यूज सिवनी। मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार जनपद पंचायत लखनादौन अंतर्गत 12 जून से 14 जून 2026 तक तीन दिवसीय विशेष जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर भारत सरकार एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

शिविर के सफल आयोजन हेतु ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं कोटवारों द्वारा गांव-गांव में डोंडी पिटवाकर एवं मुनादी कराकर नागरिकों को शिविर की जानकारी दी गई। वहीं सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा सर्वे कर विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए। तीन दिवसीय शिविर में विभिन्न विभागों के खण्ड स्तरीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आमजन की समस्याओं एवं योजनाओं से संबंधित आवेदनों का निराकरण किया गया। शिविर के दौरान कुल 9029 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 8450 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। शेष 579 आवेदन लंबित हैं, जिनका निराकरण संबंधित विभागों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। जनपद पंचायत लखनादौन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि विशेष जन कल्याण शिविरों के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।

झमाझम बारिश से किसानों को मिली राहत, मुख्यालय में रिमझिम बारिश ने बढ़ाई उमस

सिवनी/छपारा: जिले के छपारा और लखनादौन क्षेत्र में रविवार शाम हुई झमाझम बारिश ने एक ओर जहां भीषण गर्मी से लोगों को राहत दी है, वहीं खेतों में बोवनी का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी है। हालांकि इस तेज बारिश और आंधी-तूफान ने जहां कृषि कार्य को संजीवनी दी है, वहीं स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद के इंतजामों की पोल भी खोलकर रख दी है।

लंबे समय से मानसून का इंतजार कर रहे किसानों ने छपारा क्षेत्र में मक्का आदि की बुवाई कर दी थी। रविवार शाम करीब 6 बजे हुई तेज बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली। यद्यपि जिले में अभी मानसून पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ है और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 22 जून तक इसके पूरी तरह स्थापित होने का पूर्वानुमान है। जिले के किसान खाद-बीज और कीटनाशक की व्यवस्था कर मानसून की मुख्य बारिश का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ छपारा के बाद सिवनी नगर में भी रात करीब 8 बजे गरज-चमक के साथ हल्की रिमझिम बारिश हुई, लेकिन कुछ ही देर में पानी थमने से वातावरण में उमस बढ़ गई।

तेज बारिश ने छपारा नगर परिषद की लापरवाही को उजागर कर दिया। जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण नगर के कई वार्डों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई और नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि जब मानसून की शुरुआत और हल्की बारिश में ही यह हाल है, तो आगामी तीन महीनों की झमाझम बारिश में स्थिति और अधिक खराब हो सकती है। यदि परिषद ने समय रहते सुधार नहीं किया तो नगरवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

रविवार शाम आए इस तेज आंधी-तूफान में छपारा में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। नगर की सिंचाई कालोनी स्थित करीब 40 वर्ष पुराने जर्जर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास की छत पर लगा टीन का छप्पर तूफान में कागज की तरह उड़ गया। गनीमत यह रही कि शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के कारण वर्तमान में छात्रावास खाली था, अन्यथा जनहानि हो सकती थी। तेज हवाओं के कारण छत के टीन उडक़र बिजली के तारों में जा फंसे और दूर जा गिरे। इसके अलावा भवन के अंदर रखे पलंग, गद्दे और अन्य सामान भी क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि इस कच्ची मिट्टी की दीवारों वाले जर्जर भवन की दो वर्ष पूर्व जनजातीय कार्य विभाग ने मरम्मत कराई थी। इस घटना के बाद केवल रंग-रोगन कर इतने जर्जर भवन में छात्रों को रखने और उनकी सुरक्षा के साथ जोखिम उठाने को लेकर विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

रखरखाव के अभाव में जर्जर हो रहा वेनगंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स

छत पर उगे पीपल के पेड़ों से बढ़ रहा नुकसान, दुकानों के साथ आवासीय फ्लैटों पर भी असर

हरिभूमि न्यूज ⏭ सिवनी।

शहर के प्राइवेट बस स्टैंड के समीप स्थित वेनगंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वर्षों से रखरखाव के अभाव का शिकार है। हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित इस परिसर में निचले हिस्से में दुकानें और ऊपरी मंजिलों पर आवासीय फ्लैट बने हुए हैं। समय के साथ भवन की हालत लगातार बिगड़ती गई, लेकिन इसके संरक्षण और मरम्मत की दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए। नतीजतन अब कॉम्प्लेक्स की छत और ऊपरी हिस्सों में पीपल के पेड़ उग आए हैं, जिनकी जड़ें भवन की संरचना को प्रभावित कर रही हैं। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले भवन की स्थिति को लेकर रहवासियों और व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है।

शहर के प्रमुख व्यावसायिक और आवासीय परिसरों में शामिल वेनगंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कई वर्ष पहले किया गया था। परिसर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। इसके बावजूद नियमित मेंटेनेंस के अभाव में भवन के कई हिस्सों में जर्जरता के संकेत दिखाई देने लगे हैं। छत और ऊपरी मंजिलों पर उगे पीपल के पेड़ इसकी बदहाल स्थिति को दर्शा रहे हैं। भवन की दीवारों और छत के कुछ हिस्सों पर भी समय के असर के निशान दिखाई देने लगे हैं।

समय पर नहीं हुई देखरेख

स्थानीय लोगों के अनुसार कॉम्प्लेक्स के निर्माण के बाद शुरुआती वर्षों में इसकी स्थिति बेहतर थी, लेकिन समय के साथ रखरखाव की व्यवस्था कमजोर पड़ती गई। छत पर जमा मिट्टी, धूल और नमी के कारण छोटे पौधे उगने लगे। समय रहते उनकी सफाई नहीं कराई गई, जिससे अब कई स्थानों पर पीपल के पेड़ विकसित हो चुके हैं। इन पेड़ों की जड़ें कंक्रीट और दीवारों के भीतर तक पहुंच रही हैं, जिससे भवन को नुकसान पहुंच रहा है। भवनों की छत और दीवारों में उगने वाले पीपल के पेड़ समय के साथ निर्माण सामग्री को प्रभावित करते हैं। लगातार बढ़ती जड़ों के कारण दरारें और अन्य नुकसान होने की संभावना भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि ऐसे पेड़ों को प्रारंभिक अवस्था में ही हटाने की आवश्यकता होती है।

बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में भवन के जिन हिस्सों में दरारें और क्षति दिखाई दे रही है, वहां पानी पहुंचने से नुकसान और बढ़ सकता है। लगातार नमी मिलने से छत पर उगे पेड़ों की वृद्धि भी तेज हो सकती है। इससे भवन की स्थिति और खराब होने की आशंका बनी हुई है।

कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान कई स्थानों पर सीलन और पानी रिसने जैसी समस्याएं सामने आती हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि भवन की बिगड़ती स्थिति का असर पूरे परिसर पर दिखाई दे रहा है।

मेंटेनेंस को लेकर एक-दूसरे पर जिम्मेदारी

कॉम्प्लेक्स के रखरखाव को लेकर स्थिति लंबे समय से स्पष्ट नहीं हो सकी है। नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारी भवन के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी हाउसिंग बोर्ड की बताते हैं, जबकि हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी इस संबंध में नगरपालिका की भूमिका का हवाला देते हैं। दोनों विभागों के बीच जिम्मेदारी तय नहीं होने से आवश्यक मरम्मत और रखरखाव का कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

दुर्व्यवहार का लगाया आरोप, भोपाल में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों का सौंपेंगे ज्ञापन

सीईओ अभिषेक सराफ को हटाने जिपं सदस्य लामबंद

हरिभूमि न्यूज बालाघाट।

बालाघाट जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ को हटाने की मांग को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य भोपाल रवाना हो रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के सदस्य एकजुट होकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात करेंगे। सदस्यों ने सीईओ के खराब व्यवहार और एई शिव भास्कर के बिना काम न होने का आरोप लगाया है।

यह विवाद 19 मई शुक्रवार को जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक के दौरान शुरू हुआ था। उस समय विधायक प्रतिनिधि और सीईओ के बीच सवाल-जवाब को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद सीईओ अभिषेक सराफ बैठक छोड़कर चले गए थे। इस घटना के बाद से ही भाजपा और कांग्रेस से जुड़े जिला पंचायत सदस्य सीईओ को हटाने की मांग पर एकजुट हो गए हैं।

इसी सिलसिले में सोमवार शाम 5 बजे जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार के शासकीय बंगले पर सदस्यों की बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि सभी सदस्य भोपाल जाकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलेंगे और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि सीईओ को नहीं हटाया गया तो मुख्यालय में आंदोलन किया जाएगा।

जिला पंचायत सदस्य ज्योति उमरे ने बताया कि सीईओ अभिषेक सराफ का व्यवहार हमेशा से खराब रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला पंचायत में महिला सदस्यों से बात करने का उनका लहजा ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बैठकों में सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का न तो सही जवाब दिया जाता है और न ही उनका निराकरण होता है।

उमरे ने आगे बताया कि जिला पंचायत

में एई शिव भास्कर के अलावा कोई काम नहीं होता है। सदस्यों का आरोप है कि सभी कार्य शिव भास्कर के माध्यम से ही होते हैं, जिससे अन्य अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठते हैं।

इस संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने बताया कि सभी सदस्य सीईओ अभिषेक सराफ को हटाने के लिए एकजुट हैं। उन्होंने एई शिव भास्कर के बारे में कहा कि वह पहले ही हट गए थे, लेकिन जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं को उनकी जरूरत थी, क्योंकि उनके बिना कई काम अटक जाते हैं।

जिला पंचायत प्रतिनिधियों के नाम लिए जाने पर एई शिव भास्कर ने चर्चा करते हुए बताया कि मुझ पर जो पंचायत के कार्यो के मूल्यांकन करने का आरोप लगाया जा रहा है, वह गलत है, मैंने आज तक किसी भी पंचायत का मूल्यांकन नहीं किया है और मेरे बिना काम नहीं होते के आरोप भी गलत है, क्योंकि मैं तो डीएमएफ में केवल एई हूं, अधिकारी हूं नहीं कि मेरे बिना काम ना हो सके।

बाजारी चौक जाम में सड़कों पर बह रहा गंदा पानी, बदबू से लोगों का जीना मुहाल

प्रशासन की बड़ी लापरवाही, महामारी फैलने का बढ़ा खतरा?व्यापारी और राहगीर परेशान

हरिभूमि न्यूज लालबर्रा। विकासखंड लालबर्रा अंतर्गत ग्राम जाम के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक, बाजारी चौक पर पिछले कई दिनों से गंदा और बदबूदार पानी सड़कों पर बह रहा है। इस गंभीर समस्या के कारण स्थानीय निवासियों, दुकानदारों और राहगीरों का पैदल चलना भी दूषित और मुहाल हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि /प्रशासन को बार-बार शिकायत करने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।विस्तृत जानकारी बाजारी चौक एक मुख्य व्यावसायिक केंद्र है, जहाँ रोज़ हजारों लोगों का आना-जाना होता है। ब्लॉकेज के कारण गंदा पानी सड़क के बीचों-बीच जमा हो रहा है।

बीमारियों का खतरा : तेज धूप और गर्मी के कारण इस पानी से भीषण सड़ांध और बदबू आ रही है। इससे इलाके में मलेरिया, डेंगू और डायरिया जैसी बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। दुकानों के ठीक सामने गंदा पानी और कीचड़ जमा होने से ग्राहक यहाँ आने से कतरा रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों का धंधा चौपट हो रहा है। पानी और काई की वजह से सड़क पर फिसलन हो गई है, जिससे दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटील भी हो सकते हैं।

समान नागरिक संहिता पर आनलाइन सुझाव आमंत्रित

शासकीय अधिकारी-कर्मचारी सहित सभी वर्गों के नागरिक दे सकते हैं अपनी राय

हरिभूमि न्यूज बालाघाट। राज्य शासन द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में आम नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए विशेष रूप से तैयार की गई वेबसाइट पर नागरिक अपने सुझाव ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।

समान नागरिक संहिता के विभिन्न पहलुओं पर जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इस प्रक्रिया में आम नागरिकों के साथ-साथ शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य, समाजसेवी, स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि, मीडिया कर्मी तथा सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य संगठनों से जुड़े लोग भी अपनी राय दर्ज करा सकेंगे। सुझाव देने के लिए नागरिकों को वेबसाइट ucc.mp.gov.in पर जाकर निर्धारित ऑनलाइन प्रपत्र भरना होगा। प्रपत्र में नाम, लिंग, धर्म, संभाग, जिला, पता और मोबाइल नंबर जैसी सामान्य जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद समान नागरिक संहिता से संबंधित 12 प्रश्नों के उत्तर 'हाँ' अथवा 'नहीं' में देने होंगे।

ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। ओटीपी सत्यापन के साथ ही सुझाव सफलतापूर्वक दर्ज हो जाएगा। राज्य शासन ने अधिक से अधिक नागरिकों से इस प्रक्रिया में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव साझा करने की अपील की है, ताकि समान नागरिक संहिता के संबंध में व्यापक जनमत प्राप्त किया जा सके और विभिन्न वर्गों की राय को संकलित किया जा सके।

समान नागरिक संहिता पर आम जन से अपने सुझाव शीघ्रता से दर्ज कराने की अपील की गई है। इच्छुक नागरिक समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन माध्यम से अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं।

प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु जिलेभर में चलेगा विशेष अभियान

बालाघाट। भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित ₹ज्ञान भारतम्-मिशन₹ के तहत बालाघाट जिले में प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों की खोज, दस्तावेजीकरण एवं डिजिटलीकरण के लिए व्यापक अभियान शुरू किया जा रहा है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने सभी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों एवं राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर कार्यालय से जारी निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा विकसित ₹ज्ञान भारतम्-एप₹ के माध्यम से नागरिक अपने पास सुरक्षित पुरानी साहित्यिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व की हस्तलिखित पांडुलिपियों की जानकारी ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी कमिश्नरों एवं कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर दिया था। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे जिले के निजी शोध संस्थानों, महाविद्यालयों, पुस्तकालयों, मंदिरों, मठों, आश्रमों, निजी ट्रस्टों तथा अन्य संस्थाओं में संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियों की पहचान कर उनकी जानकारी ज्ञान भारतम्-एप पर दर्ज करवाएं। इसके साथ ही आम नागरिकों को भी इस अभियान से जोड़ने के लिए जनजागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी।गौरतलब है कि ₹ज्ञान भारतम्-मिशन₹ की घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में की गई थी। मिशन का मुख्य उद्देश्य देशभर में बिखरी हुई हस्तलिखित ज्ञान-संपदा का सर्वेक्षण कर उसे डिजिटल स्वरूप में संरक्षित करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रह सके। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके पास किसी भी प्रकार की प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपि उपलब्ध हो, तो उसकी जानकारी ज्ञान भारतम्-एप पर अपलोड कर इस राष्ट्रीय अभियान में सहभागी बनें। प्रशासन का मानना है कि जनसहयोग से जिले में उपलब्ध दुर्लभ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।

श्री भलावी ने जिला आपूर्ति अधिकारी का पदभार संभाला

बालाघाट। मण्डला से स्थानांतरित होकर आये श्री संत कुमार भलावी ने 22 जून को जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी बालाघाट का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। बालाघाट में पदस्थ आपूर्ति अधिकारी आरके ठाकुर का कटनी स्थानांतरण हो गया है।

2024 मॉडल का ट्रैक्टर 2025 बताकर बेचा, आरसी में खुली पोल

ट्रैक्टर बिक्री में एजेंट पर धोखाधड़ी का आरोप

हरिभूमि न्यूज कटंगी।

ट्रैक्टर बिक्री में धोखाधड़ी और जातिसूचक गाली-गलौज का मामला सामने आया है। तिरोड़ी तहसील के ग्राम पौनिया निवासी सुकचंद पिता बाबूराव जगने ने ग्राम कोहका निवासी एजेंट महेश राहंगडाले के खिलाफ कटंगी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और एससी-एसटी एक्ट की गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पीड़ित सुकचंद जगने ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने 8 मई 2025 को एजेंट महेश राहंगडाले के जरिए महिंद्रा कंपनी का एक ट्रैक्टर खरीदा था। खरीद के समय ट्रैक्टर पर निर्माण अवधि जुलाई 2024 दर्ज थी। सुकचंद ने जब एजेंट महेश को फोन पर यह बात बताई तो उसने घर आकर ट्रैक्टर देखा और आश्वासन दिया कि वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र यानी आरसी बुक में 2025 मॉडल ही दर्ज होगा। एजेंट ने आरसी आने तक इंतजार करने को कहा। 15 जून 2026 को बालाघाट स्थित महिंद्रा ट्रैक्टर शोरूम से सुकचंद को आरसी लेने के लिए कॉल आया। 16 जून को जब सुकचंद शोरूम पहुंचे तो आरसी में ट्रैक्टर के निर्माण का वर्ष 2024 ही दर्ज था। आपत्ति जताने पर शोरूम संचालक ने एजेंट महेश से बात करने को कहा। सुकचंद ने महेश को फोन कर पूरी बात बताई और बालाघाट शोरूम आने के लिए कहा। लेकिन महेश ने बालाघाट आने से इनकार कर दिया और कंपनी से बात करने की सलाह देकर पल्ला झाड़ लिया। निराश होकर सुकचंद अपने भतीजे विशाल जगने के साथ ग्राम पौनिया लौट रहे थे। रास्ते में जोडसड़क पावर हाउस के पास उन्हें एजेंट महेश राहंगडाले मिल गया। सुकचंद ने उससे आरसी में 2024 की जगह 2025 मॉडल दर्ज कराने की बात कही। आरोप है कि इस पर महेश भड़क गया और सुकचंद के साथ अश्लील, गंदी-गंदी और जातिसूचक गालियां देने लगा। पीड़ित का आरोप है कि महेश ने उसके साथ धक्का-मुक्की भी की और जान से मारने की धमकी दी।

इन धाराओं में हुई कार्रवाई: पीड़ित सुकचंद जगने ने 21 जून को कटंगी थाने पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी महेश राहंगडाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296(ए), 351(3), और अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(वीए) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। ट्रैक्टर के दस्तावेज, बिक्री संबंधी कागजात और आरसी की जांच की जा रही है।

नगर पालिका स्थापना दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाया

हरिभूमि न्यूज बालाघाट । नगर पालिका परिषद मलाजखंड ने 22 जून सोमवार को नगर पालिका के स्थापना दिवस को गौरव दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी के प्रतिमा दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नगर पालिका परिषद मलाजखंड की स्थापना 22 जून 1995 को की गई थीं। इसके लिए प्रतिवर्ष 22 जून को नगर पालिका परिषद गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौरव दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम भी लगाया गया। इसके साथ ही नगर गौरव दिवस के अवसर पर राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने नगर पालिका को उपहार भेंट किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष मानसिंह मेरावी, सभापति मधु सेन्दरे, सुबदारसिंह कुशवाहा, सरला मेरावी, पार्षद विजयसिंह राठौर, विजय धुर्वे, पूर्व पार्षद पूरन चौधरी, शिवप्यारी तोमर, संजय श्रीवास, सीएमओ दिनेश बाघमारे सहित अधिकारी, कर्मचारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

जामिया नूरिया, बालाघाट में लगा निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर

सरदार पटेल मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की जनसेवा पहल को मिला अभूतपूर्व जनसमर्थन

हरिभूमि न्यूज बालाघाट। सेवा, समर्पण, विश्वास के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए सरदार पटेल मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, गायखुरी, बालाघाट द्वारा जामिया नूरिया प्रबंधन समिति के सहयोग से जामिया नूरिया, बहियार रोड, बालाघाट में एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के सैकड़ों नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाओं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त किया। शिविर के दौरान नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श, रक्तचाप (बी.पी.) जांच, बोन मिनरल डेंसिटी (बीएमडी) जांच, विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण, दवा वितरण तथा स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रदान किए गए।

विशेषज्ञ चिकित्सकों ने दी अपनी सेवाएं

शिविर में सरदार पटेल मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कीं—डॉ. प्रिंस वर्मा – ब्रेन एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ, डॉ. शुभम वैद्य – ऑर्थोपेडिक एवं हिप-जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, डॉ. प्रवीण जयराजन – मेडिसिन विशेषज्ञ, डॉ. उमंग बघेल – जनरल फिजिशियन एवं पैथोलॉजिस्ट, डॉ. निकलेश वासनिक – जनरल सर्जन, डॉ. रश्मि सकारवाड़े – स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।

विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों की स्वास्थ्य समस्याओं का गहन परीक्षण कर आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श एवं उपचार संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। साथ ही अनेक गंभीर बीमारियों की प्रारंभिक पहचान कर समय पर उपचार एवं स्वास्थ्य जागरूकता के लिए प्रेरित किया गया।

आयुष्मान भारत एवं राहत योजनाओं की दी जानकारी

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना एवं प्रधानमंत्री राहत योजना के अंतर्गत उपलब्ध निःशुल्क एवं रियायती उपचार सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। पात्र हितग्राहियों को इन योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने हेतु जागरूक एवं प्रेरित किया गया।

सार्वजनिक नाली व आवागमन मार्ग अवरुद्ध करने का मामला, पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई के निर्देश

लांजी में नाली विवाद पर प्रशासन सख्त, अवैध ईंट-मलबा हटाने एसडीएम का आदेश

हरिभूमि न्यूज लांजी। लांजी नगर के वार्ड क्रमांक 03 में सार्वजनिक नाली एवं आवागमन मार्ग अवरुद्ध किए जाने के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। 11 जून को लांजी एसडीएम ने मामले की जांच के बाद अवैध रूप से रखी गई ईंट एवं मलबा हटाने के निर्देश जारी किए हैं। मामला वार्ड क्रमांक 03 निवासी सुनील कुमार शर्मा, पिता जुगल किशोर शर्मा, और पड़ोसी पक्ष चंद्रकिरण ठाकरे पति प्रेमलाल ठाकरे, जतिन ठाकरे, सुमित ठाकरे तथा अमित ठाकरे के बीच का है। सुनील कुमार शर्मा ने प्रशासन को शिकायत देकर बताया था कि उनकी माता शकुंतला शर्मा के नाम दर्ज मकान एवं अनावेदक पक्ष के मकान के बीच स्थित सार्वजनिक गली एवं नाली (ड्रेनेज चैनल) को ईंट और मलबा रखकर बाधित कर दिया गया है। आवेदक का आरोप है कि इस अवरोध के कारण बरसाती पानी की निकासी रुक रही है और उनके मकान के पीछे के हिस्से तक

पहुंचना भी कठिन हो गया है। साथ ही बरसात के दौरान मकान को नुकसान और जन-धन हानि की आशंका भी बढ़ गई है।

शिकायत के बाद प्रशासन द्वारा संयुक्त जांच दल गठित कर मौके का निरीक्षण कराया गया। जांच में पाया गया कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से नाली और मलबे को लेकर विवाद बना हुआ है। निरीक्षण के दौरान दोनों पक्ष उपस्थित रहे। जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया कि अनावेदक पक्ष द्वारा आवेदक के मकान से सटाकर ईंट और मलबा रखा गया है। अधिकारियों ने अनावेदक पक्ष को समझाइश दी कि बरसात से पहले ईंट हटाना आवश्यक है, ताकि किसी प्रकार की हानि से बचा जा सके। हालांकि अनावेदकों ने पूर्व से सिविल विवाद लंबित होने का हवाला देते हुए स्वयं हटाने से इंकार कर दिया।

प्रकरण के परीक्षण के बाद एसडीएम न्यायालय ने माना कि सार्वजनिक नाली और आवागमन मार्ग पर रखा गया ईंट-मलबा अवैध अवरोध की श्रेणी में आता है। आदेश में नगर परिषद लांजी, तहसीलदार कार्यालय लांजी तथा पुलिस थाना लांजी को संयुक्त रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक पुलिस बल की उपस्थिति में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रखी गई ईंट और मलबा हटाया जाए तथा कार्रवाई पूर्ण होने के बाद पालन प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। प्रशासन के इस आदेश के बाद क्षेत्र में विवाद के जल्द समाधान की उम्मीद बढ़ गई है।

सिविल कोर्ट में मामला लंबित, प्रशासनिक कार्रवाई पर उठे सवाल: वहीं जमीन विवाद को लेकर चन्द्रकिरण पति प्रेमलाल ठाकरे ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय की मांग की है। चन्द्रकिरण ठाकरे ने बताया कि सुनील शर्मा द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा किया गया है और यह मामला वर्तमान में सिविल कोर्ट बालाघाट में विचाराधीन है। उनका कहना है कि इस संबंध में उन्होंने पूर्व में एसडीएम साहब को भी अवगत कराया था, लेकिन इसके बावजूद उनकी ही जमीन से ईंट सहित अन्य सामग्री हटवाकर कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। चन्द्रकिरण ठाकरे का आरोप है कि पुलिस प्रशासन सहित अन्य अमले द्वारा उनके साथ दुव्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि एसडीएम सहित सभी अधिकारियों को यह जानकारी है कि दस्तावेजों में कहीं भी सुनील शर्मा का नाम दर्ज नहीं है, फिर भी उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। उनका कहना है कि सुनील शर्मा एक जिलाबदल व्यक्ति है और पिछले 10 से 12 वर्षों से उनकी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं।